



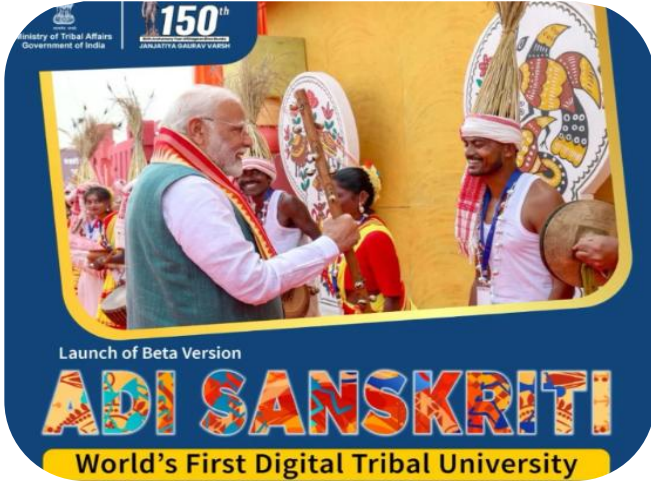
Daily करेंट अफेयर्स

➤ 13 सितम्बर 2025



NATIONAL AFFAIRS

1. MoTA ने भारत मंडपम में जनजातीय कला रूपों के लिए 'आदि संस्कृति' डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।



सितंबर 2025 में, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आदि संस्कृति का बीटा संस्करण लॉन्च किया। यह आदिवासी कला, संस्कृति और सतत आजीविका को समर्पित एक डिजिटल शिक्षण मंच है।

• इस मंच को आधिकारिक तौर पर जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर आदिवासी संस्कृति, आजीविका और शिल्प को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय बनाना है।

• आदि संस्कृति तीन प्रमुख खंडों को एकीकृत करती है - आदि विश्वविद्यालय (डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकादमी जो 45 इमर्सिव पाठ्यक्रम प्रदान करती है), आदि संपदा (आदिवासी विरासत पर 5,000 से अधिक क्यूरेटेड दस्तावेजों के साथ एक सामाजिक-सांस्कृतिक भंडार), और आदि हाट (एक ऑनलाइन बाज़ार जो वर्तमान में ट्राइफेड से जुड़ा हुआ है)।

• यह पहल 12 राज्यों के राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRIs) के साथ साझेदारी में विकसित की गई है, जिससे जनजातीय परंपराओं में जमीनी स्तर पर भागीदारी, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

Key Points:-

(i) इसके पहले चरण में, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों के TRIs ने सांस्कृतिक मानचित्रण और डिजिटल दस्तावेजीकरण में योगदान दिया है।

(ii) यह मंच आदि कर्मयोगी अभियान का समर्थन करता है, जो विकेन्द्रीकृत जनजातीय नेतृत्व के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में 20 लाख परिवर्तनकर्ताओं को सशक्त बनाना है, जिसमें 1 लाख गांवों को कौशल-आधारित क्षमता निर्माण और उद्यमिता पहलों में शामिल किया गया है।

(iii) अगस्त 2025 में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के लिए भारत के पहले एआई-संचालित अनुवादक आदि वाणी की भी घोषणा की, जो भाषाई अंतराल को पाटने और लुप्तप्राय बोलियों के संरक्षण के लिए आधार तैयार करेगा।

2. केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रेक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया।



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रेक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम (FTI-TTP) का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम तेज़, सुगम और सुरक्षित इमिग्रेशन क्लियरेंस के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्री गतिशीलता को बढ़ाता है।

- FTI-TTP को भारतीय नागरिकों और विदेश से आने वाले प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) के लिए तेज़ और परेशानी मुक्त आव्रजन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ई-गेट्स (स्वचालित सीमा द्वार) पर काम करता है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और सुविधा व राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों मज़बूत होती हैं।

- यह कार्यक्रम सबसे पहले 2023 में दिल्ली हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था, और अब इसका विस्तार देश भर के 13 हवाई अड्डों तक हो गया है, जिनमें सितंबर 2025 में अमित शाह द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले पांच हवाई अड्डे भी शामिल हैं। इस विस्तार का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से भारत के सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को कवर करना है।

- अब तक 3 लाख यात्रियों ने FTI-TTP पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जो भारतीय और विदेशी यात्रियों के बीच स्वचालित आव्रजन समाधानों को अपनाने में वृद्धि दर्शाता है।

Key Points:-

(i) अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2014 में, 3.54 करोड़ भारतीयों ने विदेश यात्रा की, जो 2024 में 73% बढ़कर 6.12 करोड़ हो गई, जो भारत की बढ़ती वैश्विक गतिशीलता को दर्शाता है।

(ii) भारत आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2014 में 1.53 करोड़ विदेशी यात्री भारत आए थे, जो 2024 में बढ़कर 2 करोड़ हो गए, जो भारत के बढ़ते वैश्विक आकर्षण को दर्शाता है।

(iii) प्रौद्योगिकी-संचालित दक्षता को उन्नत सीमा सुरक्षा के साथ जोड़कर, FTI-TTP भारत की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अवसंरचना को मजबूत करता है, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देता है, और भारत के डिजिटल शासन और स्मार्ट सीमा प्रबंधन के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है।

3. CCEA ने भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण और बक्सर-भागलपुर HSR कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को मंजूरी दी।



10 सितंबर 2025 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में

कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेलवे दोहरीकरण और एक नए हाई-स्पीड कॉरिडोर खंड सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी।

- सीसीई ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले 177 किलोमीटर भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट एकल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 3,169 करोड़ रुपये है।

- यह मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना 5 जिलों को कवर करेगी, जिससे 441 गाँवों और लगभग 2.87 लाख लोगों को लाभ होगा। यह बांका, गोड्डा और दुमका जैसे महत्वाकांक्षी जिलों को भी जोड़ेगी और देवघर जैसे गंतव्यों के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

- उन्नत लाइन व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम करेगी, कोयला, सीमेंट, उर्वरक और ईंटों की माल ढुलाई को बढ़ाएगी और परिचालन दक्षता में सुधार करेगी, जो सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

Key Points:-

(i) सीसीई ने हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के तहत बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर के 82.4 किलोमीटर लंबे 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-नियंत्रित मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसकी लागत 4,447.38 करोड़ रुपये है।

(ii) यह गलियारा 100 किमी/घंटा तक की गति के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह मोकामा, बरहिया, लखीसराय और जमालपुर जैसे प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ेगा, जिससे यात्रा का समय 1-1.5 घंटे कम हो जाएगा।

(iii) यह परियोजना औद्योगिक समूहों तक पहुँच में सुधार और वस्तुओं एवं सेवाओं की तीव्र आवाजाही को बढ़ावा देकर पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। यह परिवहन अवसंरचना को एकीकृत करके प्रधानमंत्री गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान

(पीएम गति शक्ति - एनएमपी) को मज़बूत करेगी।

4. सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए MoRTH ने ज़ोमैटो और उबर के साथ सहयोग किया।



सत्यमेव जयते
MoRTH

Ministry of Road Transport
and Highways

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पूरे भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2025 में ज़ोमैटो और उबर के साथ साझेदारी की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में यह पहल भारत सरकार के 'सड़क सुरक्षा अभियान' के तीसरे वर्ष का प्रतीक है।

- इस समझौते का अनावरण नई दिल्ली में आयोजित एक सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान किया गया, जिसका आयोजन ज़ोमैटो और उबर ने संयुक्त रूप से किया था, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला।

- इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप, 2030 तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे संबंधित मौतों को 50% तक कम करना है।

- ज़ोमैटो अपने डिलीवरी पार्टनर ऐप और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सड़क सुरक्षा संदेश फैलाएगा, तथा उपयोगकर्ताओं और

डिलीवरी कर्मियों के साथ दैनिक बातचीत में सुरक्षा युक्तियों को एकीकृत करेगा।

Key Points:-

- (i) उबर चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा, सवारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देगा, तथा अपने ऐप के माध्यम से सड़क सुरक्षा युक्तियां साझा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सुरक्षा प्रथाओं को उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में सुदृढ़ किया जाए।
- (ii) यह सहयोग 2023 में लॉन्च किए गए सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का समर्थन करता है, जिसकी थीम "परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे" (दूसरों की देखभाल, सुरक्षित रहें) है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने जागरूकता अभियानों में भाग लिया था।
- (iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 4.2% की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.8 लाख मामलों को पार कर गई, तथा प्रति घंटे 20 मौतों की खतरनाक दर रही, जो इस पहल की तात्कालिकता को रेखांकित करती है।

5. IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोला, जिसका उद्घाटन दुबई के क्राउन प्रिंस ने किया।



भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूल, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIMA) ने दुबई में अपने पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है, जो भारत के शिक्षा वैश्वीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- दुबई के क्राउन प्रिंस और उप प्रधान मंत्री महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान की उपस्थिति में परिसर का उद्घाटन किया।
- दुबई परिसर IIMA का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है, जो भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि दुबई "भारतीय भावना, वैश्विक दृष्टिकोण" के सिद्धांत के लिए आदर्श मंच है, जो भारत-UAE शैक्षिक सहयोग को बढ़ाता है।

Key Points:-

- (i) उपस्थित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों में श्री संजय सुधीर (UAE में भारत के राजदूत), श्री सतीश सिवन (दुबई में भारत के महावाणिज्यदूत), श्री पंकज पटेल (अध्यक्ष, IIMA बोर्ड) और प्रो. भारत भास्कर (निदेशक, IIMA) शामिल थे।
- (ii) संयुक्त अरब अमीरात की ओर से, महामहिम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गर्गवी (कैबिनेट मामलों के मंत्री), महामहिम रीम अल हाशिमि (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री) और महामहिम सारा बिनत यूसुफ अल अमीरी (शिक्षा मंत्री) सहित कई मंत्री इसमें शामिल हुए।
- (iii) श्री प्रधान ने GCC देशों के CBSE स्कूलों में 12 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की भी घोषणा की, जिससे छात्रों के बीच STEM नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

6. ACME ग्रुप और जापान की IHI कॉर्पोरेशन ने ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम बनाया।



सितंबर 2025 में, ACME समूह ने जापान के IHI कॉर्पोरेशन (इशिकावाजिमा-हरिमा हेवी इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन) के साथ एक संयुक्त उद्यम (JV) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ओडिशा के गोपालपुर में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित की जाएगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होगा।

- IHI कॉर्पोरेशन संयुक्त उद्यम कंपनी ACME क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में 30% हिस्सेदारी रखेगा, जबकि ACME ग्रुप 70% हिस्सेदारी अपने पास रखेगा।

- यह संयंत्र प्रतिवर्ष 0.4 मिलियन टन (MT) हरित अमोनिया का उत्पादन करेगा, जिससे यह भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा संयंत्र बन जाएगा।

Key Points:-

(i) इस परियोजना के 2029-30 तक चालू होने की उम्मीद है। उत्पादन मुख्य रूप से बिजली और रसायन क्षेत्र की खपत के लिए जापान को निर्यात किया जाएगा।

(ii) इस परियोजना से प्रतिवर्ष 0.8 मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कटौती होने का अनुमान है, जो भारत के

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) और जापान के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों का समर्थन करता है, साथ ही रोजगार सृजन और ओडिशा को हरित ऊर्जा केंद्र के रूप में बढ़ावा देता है।

7. नमो भारत भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है, जो 60 मिनट से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ तक का सफर तय करेगी।



सितंबर 2025 में, दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस पर नमो भारत ट्रेन अपने परिचालन खंड पर 160 किमी/घंटा की शीर्ष गति प्राप्त करेगी, जिससे यह भारत की सबसे तेज ट्रेन बन जाएगी, जो दिल्ली-मेरठ की दूरी एक घंटे से भी कम समय में तय करेगी।

- न्यू अशोक नगर (दिल्ली) से मेरठ दक्षिण तक 55 किलोमीटर लंबे खंड पर 160 किमी/घंटा की गति से चलती है।

- पूरा कॉरिडोर 82.15 किलोमीटर लंबा है और इसमें दिल्ली के सराय काले खां से लेकर उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम तक 16 स्टेशन शामिल हैं।

Key Points:-

(i) इस प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि पूरी तरह चालू होने के बाद, स्टॉपेज के बावजूद, दिल्ली-मेरठ की यात्रा एक घंटे से कम समय में पूरी हो जाएगी।

(ii) छह-कार ट्रेन-सेट का निर्माण एल्स्टॉम द्वारा अपने सावली कारखाने (गुजरात) में किया गया है, जिसमें वायुगतिकीय डिजाइन है, और यह एटीपी, एटीसी और एटीओ प्रणालियों से सुसज्जित है।

(iii) रेलगाड़ियां 15 मिनट के अंतराल पर चलती हैं; स्टेशनों के बीच की दूरी 5-8 किमी तक होती है, जिससे लंबे खंडों के बीच अधिकतम गति संभव होती है।

INTERNATIONAL

1. किर्गिज गणराज्य में 44वीं RATS SCO परिषद की बैठक आयोजित हुई और भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की।



शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) परिषद की 44वीं बैठक किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में आयोजित की गई, जहां सदस्य देशों ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की।

● यह सत्र किर्गिजस्तान की अध्यक्षता में किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में आयोजित किया गया।

● RATS परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, तथा 1 सितंबर 2025 को SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद के दौरान अपनाए गए तियानजिन घोषणापत्र में इसे शामिल करने का समर्थन किया।

Key Points:-

(i) भारत का प्रतिनिधित्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) टी.वी. रविचंद्रन ने किया, जिन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और इस बात पर जोर दिया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रायोजकों, आयोजकों और वित्तपोषकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

(ii) मैंने SCO सदस्यों से दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने और बिना किसी भेदभाव के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से लड़ने का आग्रह किया है।

(iii) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में SCO राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जहां आतंकवाद के खिलाफ घोषणा को अपनाया गया था।

2. भारत ने रूस और बेलारूस में जैपड 2025 सैन्य अभ्यास के 9वें संस्करण में भाग लिया।



भारत ने रूस और बेलारूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास "ज़ापद 2025" के 9वें संस्करण में भाग लिया। यह अभ्यास 10-16 सितंबर, 2025 तक रूस के निज़नी नोवगोरोड स्थित मुलिनो प्रशिक्षण मैदान और बेलारूसी प्रशिक्षण मैदान में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मज़बूत करना और भारत-रूस संबंधों को मज़बूत करना है।

● इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना, रणनीति एवं प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना तथा आतंकवाद-रोधी समन्वय को बढ़ावा देना था।

● भारत, बांग्लादेश, ईरान, नाइजर, ताजिकिस्तान, बुर्किना फासो और अन्य सहित 22 से अधिक देश इसमें शामिल हुए। पर्यवेक्षक देशों में कंबोडिया, चीन, कज़ाकिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे।

● जैपैड का पिछला संस्करण 2021 में रूस और बेलारूस में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर रक्षात्मक और आक्रामक अभियानों का अनुकरण करने में इसकी ऐतिहासिक भूमिका जारी रही।

Key Points:-

(i) ज़ापेड (जिसका अर्थ है "पश्चिम") 1977 से सोवियत संघ और बाद में रूस द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास श्रृंखला है, जो आमतौर पर हर चार साल में आयोजित की जाती है। 2025 का संस्करण रूस और बेलारूस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

(ii) भारत ने 65 कर्मियों के साथ भाग लिया, जिनमें भारतीय थल सेना से 57, भारतीय वायु सेना (IAF) से 7 और भारतीय नौसेना से 1 शामिल था। इस दल का नेतृत्व कुमाऊँ रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया।

(iii) बेलारूस में आयोजित 2025 अभ्यास (12-16 सितंबर) में उन्नत ओरेशनल मिसाइलों सहित अमेरिकी नेतृत्व वाली हथियार प्रणालियों के विरुद्ध रक्षात्मक तत्परता का परीक्षण किया गया। इसका मुख्य ध्यान खुले/शहरी भूभाग पर संचालन, आतंकवाद-निरोध, अंतर-संचालन और उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण पर रहा।

BANKING & FINANCE

1. विश्व बैंक ने तमिलनाडु और कर्नाटक में SHORE परियोजना के लिए 212.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।



सितंबर 2025 में, विश्व बैंक (WB) के कार्यकारी निदेशक मंडल ने तमिलनाडु (TN) और कर्नाटक में तटीय प्रबंधन को बढ़ाने के लिए तटीय लचीलापन और अर्थव्यवस्था (SHORE) परियोजना को मजबूत करने के तहत 212.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।

● विश्व बैंक के अंग, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) ने 23 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्रदान किया, जिसमें 6.5 वर्ष की रियायत अवधि भी शामिल है।

● इसमें 100,000 व्यक्तियों (स्थायी पर्यटन में 70,000) को प्रशिक्षण, 30,000 हेक्टेयर समुद्री परिदृश्यों का संरक्षण, ग्रे/ग्रीन अवसंरचना और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।

● 2019 में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य था, भारत का समुद्र तट नौ राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 11,000 किलोमीटर तक फैला है, जो जलवायु जोखिमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

Key Points:-

(i) यह अनुमोदन 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े SHORE कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भारत की तटीय चुनौतियों के समाधान के लिए चरण 1 के लिए 212.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए हैं।

(ii) तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी (TNGCC) और कर्नाटक इको रेस्टोरेशन सोसाइटी (KERS) राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (SPMUs) के माध्यम से समन्वय के साथ परियोजना को कार्यान्वित करेंगे।

(iii) इस परियोजना से 100,000 लोगों को प्रत्यक्ष लाभ होगा, तथा प्लास्टिक में कमी और संरक्षण पहलों के माध्यम से 120,000 से अधिक लोग प्रभावित होंगे।

ECONOMY & BUSINESS

1. एयर इंडिया और एयर अस्ताना ने भारत-मध्य एशिया संपर्क बढ़ाने के लिए कोडशेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए।



10 सितंबर, 2025 को, एयर इंडिया और कज़ाकिस्तान की राष्ट्रीय वाहक एयर अस्ताना ने एक कोडशेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए। एयर इंडिया का 'AI' कोड अब अल्माटी-नई दिल्ली और अल्माटी-मुंबई मार्गों सहित एयर अस्ताना की उड़ानों पर दिखाई देगा।

• कोडशेयर समझौता एयर अस्ताना द्वारा संचालित अल्माटी-नई दिल्ली और अल्माटी-मुंबई उड़ानों पर लागू होता है।

• यात्री एकल टिकट बुक कर सकते हैं और एयर इंडिया और एयर अस्ताना उड़ानों में चेक-इन के माध्यम से सामान का आनंद ले सकते हैं।

• इस समझौते से अस्ताना, बिश्केक, ताशकंद और दुशांबे जैसे मध्य एशियाई शहरों तक आसान संपर्क संभव हो गया है।

Key Points:-

(i) 1932 में स्थापित, एयर इंडिया दुनिया भर में लगभग 92 गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करती है।

(ii) 2001 में स्थापित, एयर अस्ताना कज़ाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें संचालित करती है।

(iii) यह साझेदारी मध्य एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करती है और यात्रा, व्यापार और राजनयिक संबंधों का समर्थन करती है।

MOUs and Agreement

1. भारत और मैक्सिको ने फिक्की लीड्स 2025 में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



सितंबर 2025 में, भारत और मेक्सिको ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मज़बूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा मेक्सिको की व्यापार समन्वय परिषद (BCC) के अध्यक्ष फ्रांसिस्को सर्वेस डियाज़ ने नई दिल्ली में फिक्की लीड्स 2025 कार्यक्रम के दौरान की।

- यह समझौता भारत और मैक्सिको के बीच संपूरकताओं का लाभ उठाने, ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, कृषि और चिकित्सा उपकरणों में सहयोग की संभावनाओं पर केंद्रित है।

- इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार प्रवाह में तेजी लाने के लिए लगभग 1200 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करना है।

Key Points:-

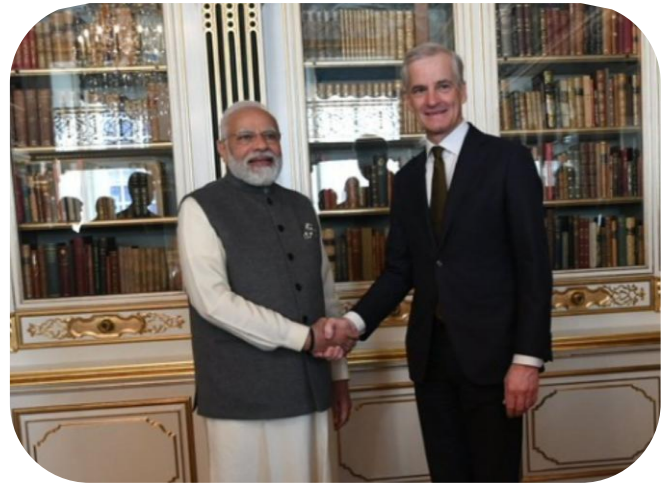
(i) 2024 में भारत-मेक्सिको व्यापार 11,711 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो बढ़ते आर्थिक जुड़ाव को दर्शाता है।

(ii) लगभग 200 भारतीय कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में मैक्सिको में 72 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया है।

(iii) उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (NAFTA) ढांचे के तहत मेक्सिको की अमेरिका और कनाडा से निकटता, इसे उत्तरी अमेरिका में भारतीय व्यवसायों के लिए एक सेतु के रूप में स्थापित करती है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. जोनास गहर स्टोरे ने नॉर्वे के प्रधान मंत्री के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल किया।



सितंबर 2025 में, नॉर्वे की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नेता जोनास गहर स्टोरे ने 8 सितंबर, 2025 को हुए संसदीय चुनावों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की।

- जोनास गहर स्टोरे ने 1989 से 1997 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सलाहकार और महानिदेशक के रूप में कार्य किया और 1995 में लेबर पार्टी में शामिल हो गये।

- मैंने 1998 से 2000 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में नॉर्वे की पहली महिला प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रुन्डलैंड के अधीन चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया है।

- वे 2005 से 2012 तक विदेश मंत्री रहे और बाद में 2013 तक स्वास्थ्य एवं देखभाल सेवा मंत्री के रूप में कार्य किया, जिससे उन्हें व्यापक शासन अनुभव प्राप्त हुआ।

Key Points:-

(i) लेबर पार्टी ने 28.2% वोट जीते और 169 में से 53 सीटें हासिल कीं, चार वामपंथी दलों के समर्थन से सत्ता बरकरार रखी।

(ii) एंटी-इमिग्रेशन प्रोग्रेस पार्टी की सिल्वी लिस्टहॉग लगभग 24% वोट और 48 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग 14.6% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर

रहीं।

(iii) जोनास गहर स्टोरे नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में अपना लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, जो अक्टूबर 2021 से लेबर पार्टी के शासन को जारी रखेंगे।

AWARDS

1. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



10 सितंबर, 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पी.वी. नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उनकी ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

• डॉ. मनमोहन सिंह ने महत्वपूर्ण आर्थिक पदों पर कार्य किया। वे 1972 से 1976 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार, 1976 से 1980 तक वित्त मंत्रालय के सचिव और 1982 से 1985 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के 15वें गवर्नर रहे।

• उन्होंने 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी रहे।

• 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में, उन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक सुधार पेश किए। ये सुधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रित थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया।

Key Points:-

(i) यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री पामुलापर्ती वेंकट (पी.वी.) नरसिम्हा राव की स्मृति में स्थापित किया गया था। उन्होंने 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उन्हें "भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक" के रूप में याद किया जाता है।

(ii) यह पुरस्कार भारत में आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों को मान्यता देता है।

(iii) डॉ. सिंह को एक अग्रणी अर्थशास्त्री और सुधारवादी के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारत के आर्थिक उदारीकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. HAL ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) के लिए ISRO, इन-स्पेस और NSIL के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए।



सितंबर 2025 में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) के निर्माण और संचालन के लिए ISRO, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) और बेंगलुरु, कर्नाटक में न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते (TTA) पर हस्ताक्षर किए, जिससे MSMEs और स्टार्ट-अप के लिए अवसर बढ़ गए।

- SSLV ISRO द्वारा विकसित एक त्रि-चरणीय प्रक्षेपण यान है, जिसे 500 किलोग्राम (किग्रा) तक के वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लागत-प्रभावी, लचीला है और छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों की बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माँग को पूरा करता है।

- इस समझौते पर HAL बेंगलूर कॉम्प्लेक्स के CEO जयकृष्णन एस; विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC)/ISRO के निदेशक ए. राजराजन; NSIL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) एम. मोहन; और IN-स्पेस के निदेशक (तकनीकी) राजीव ज्योति ने हस्ताक्षर किए। इस समारोह में अंतरिक्ष विभाग (DoS) के सचिव एवं इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन; आईएन-स्पेस के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार गोयनका; और HAL के CMD डॉ. डी. के. सुनील सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

- TTA का उद्देश्य HAL को एक घटक आपूर्तिकर्ता से पूर्ण प्रक्षेपण सेवा प्रदाता के रूप में विकसित करना है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाते हुए भारत के आत्मनिर्भर और मजबूत अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

Key Points:-

(i) HAL को SSLV तकनीक के लिए एक गैर-अनन्य, गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इस समझौते में डिज़ाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, एकीकरण, प्रक्षेपण संचालन और उड़ान-पश्चात विश्लेषण शामिल

हैं, जिससे छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए संपूर्ण क्षमताएँ सुनिश्चित होती हैं।

(ii) HAL ISRO के तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण के साथ दो साल की प्रौद्योगिकी अवशोषण अवधि से गुजरेगा, जिसके बाद दस साल की उत्पादन अवधि होगी, जिससे कंपनी भविष्य में स्वतंत्र रूप से SSLV मिशन संचालित करने में सक्षम होगी।

(iii) यह समझौता IN-SPACe द्वारा सुगम बनाए गए 100वें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को चिह्नित करता है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्टार्ट-अप्स को शामिल करने और छोटे उपग्रह प्रक्षेपण समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भारत के रणनीतिक प्रयास को दर्शाता है।

2. ISRO ने नौ विश्व रिकॉर्ड बनाए और 2040 तक मानव को चंद्रमा पर उतारने की योजना बनाई।



इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने चंद्रयान और मंगल मिशन सहित अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, साथ ही आने वाले वर्षों में 8-10 अतिरिक्त विश्व रिकॉर्ड हासिल करने की योजना की घोषणा की, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

- भारत ने अब तक अंतरिक्ष अन्वेषण में नौ बड़े विश्व रिकॉर्ड हासिल किए हैं। इनमें उल्लेखनीय

उपलब्धियाँ शामिल हैं: मंगल ऑर्बिटर मिशन (2014), जिसने भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला पहला देश बना दिया, और चंद्रयान-3 (2023), जिसने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना दिया।

- 2017 में, इसरो के PSLV-C37 मिशन ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके इतिहास रच दिया, जिसने उपग्रह प्रक्षेपण में एक वैश्विक मानक स्थापित किया। चंद्रयान-2 (2019) ने चंद्रमा के चारों ओर दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑर्बिटर कैमरा तैनात किया, जिससे भारत की चंद्र अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि हुई।

- 2014 और 2017 के बीच, भारत ने क्रायोजेनिक चरण विकास में तीन वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित किए, जिसमें क्रायोजेनिक चरण के साथ एलवीएम3 की सबसे तेज पहली उड़ान मात्र 28 महीनों में पूरी करना शामिल है, जबकि अन्य देशों को इसके लिए 37-108 महीने लगते थे।

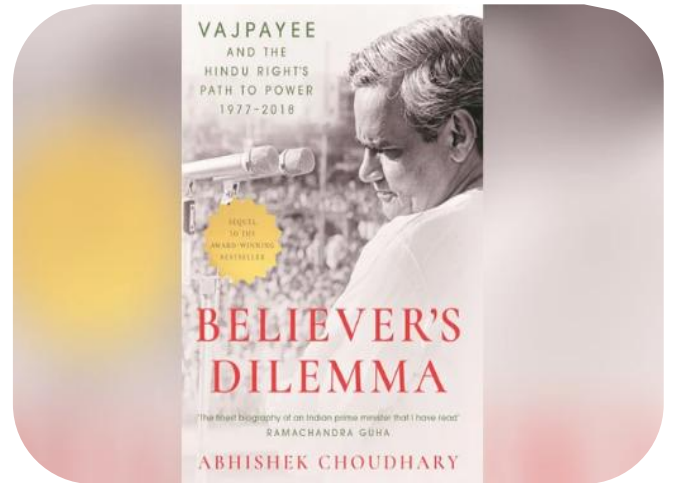
Key Points:-

(i) ISRO के लागत-संवेदनशील दृष्टिकोण ने प्रक्षेपण व्यय को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया है, जिससे भारत 4,000 से अधिक रॉकेट और 133 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सका है। ये प्रयास राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतरिक्ष उद्यमिता के विस्तार में योगदान करते हैं।

(ii) भविष्य की ओर देखते हुए, ISRO का लक्ष्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 8-10 अतिरिक्त विश्व रिकॉर्ड हासिल करना है और 2040 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने का लक्ष्य है, जो भारत की विकसित राष्ट्र बनने की महत्वाकांक्षा में एक बड़ा कदम होगा।

BOOKS & AUTHORS

1. नई जीवनी "विश्वासियों की दुविधा" अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा का वृत्तांत है।



सितंबर 2025 में, अभिषेक चौधरी द्वारा लिखित "बिलीवर्स डिलेमा: वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर (1977-2018)" नामक एक नई जीवनी का विमोचन हुआ। पिकाडोर इंडिया द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक और वैचारिक यात्रा का वर्णन करती है।

- यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की दो-खंड की जीवनी का दूसरा भाग है, जिसमें 1977 से 2018 तक के वर्षों को शामिल किया गया है। पहला खंड, वाजपेयी: द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट (1924-1977), 2022 में प्रकाशित हुआ था।

- जीवनी में वाजपेयी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारक से लेकर एक उदारवादी नेता बनने तक के सफर को दर्शाया गया है, जिन्होंने हिंदू दक्षिणपंथ को भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Key Points:-

(i) पुस्तक में जनता गठबंधन में उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाओं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठन और विकास, तथा प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल (1996, 1998-2004) के दौरान गठबंधन

प्रबंधन में उनकी रणनीतियों का वर्णन किया गया है।

(ii) इसमें वाजपेयी से जुड़ी प्रमुख घटनाओं पर चर्चा की गई है, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस और भारत के परमाणु परीक्षण शामिल हैं, तथा राजनीतिक विचारधारा और शासन के बीच संतुलन बनाने के उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है।

(iii) यह जीवनी भारत की विदेश नीति, आर्थिक सुधारों में वाजपेयी के योगदान और विविध राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए राष्ट्र के आधुनिकीकरण के उनके प्रयासों की जांच करती है।

Static GK

Ministry of Tribal Affairs (MoTA)	मंत्री: दुर्गा दास उइके	मुख्यालय : नई दिल्ली
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH)	मंत्री: नितिन गडकरी	मुख्यालय: नई दिल्ली
ISRO	अध्यक्ष: डॉ. वी. नारायणन	मुख्यालय: बेंगलुरु
Kyrgyz	राजधानी: बिश्केक	मुद्रा: किर्गिस्तानी सोम
Belarus	राष्ट्रपति : अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच लुकाशेंको	राजधानी : मिन्स्क
World Bank	अध्यक्ष: अजय बंगा	मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
P.V. Narasimha Rao Memorial Foundation (PVNMF)	अध्यक्ष : के. रामचंद्र	मुख्यालय : हैदराबाद, तेलंगाना
Norway	प्रधान मंत्री: जोनास गहर स्टोरे	राजधानी: ओस्लो